

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 का विविध आपराधिक सं. 39563

थाना कांड संख्या-2679 वर्ष 2015 थाना-भागलपुर शिकायत मामला जिला-भागलपुर से
उत्पन्न

=====

1. डॉ. राजीव रंजन सिंह, पुत्र- रमनी मोहन सिंह
2. बुलबुल देवी उर्फ वूबूल सिंह, पत्नी-डॉ. राजीव रंजन सिंह
3. रमनी मोहन सिंह, पुत्र- स्वर्गीय भुनेश्वर प्रसाद सिंह
4. महारानी देवी, पत्नी- रमनी मोहन सिंह
5. डॉ. दीपक कुमार सिंह, पुत्र- रमनी मोहन सिंह
6. श्रवण कुमार सिंह, पुत्र- गणेश प्रसाद सिंह, सभी निवासी- गाँव पकारियां, थाना-शंभूगंज,
जिला-बांका

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य
2. मिम्मी कुमारी, पत्नी- डॉ. राहुल रंजन सिंह, पुत्री- श्री विमल कुमार सिंह, वर्तमान में
क्वार्टर नंबर 221, सी. डी. वर्कशॉप रोड, पूर्व कॉलोनी, थाना-जमालपुर, जिला- मुंगेर

.....विपरीत/पक्षों

=====

उपस्थिति :

याचिकाकर्ताओं के लिए :

श्री रवीन्द्र कुमार, अधिवक्ता

श्री राकेश कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

सुश्री देवयानी शेखर, अधिवक्ता।

राज्य के लिए :

श्री डॉ. कुमार उदय प्रताप, सहायक लोक अभियोजक

विरोधी पक्ष के लिए :

श्री संजीव कुमार, अधिवक्ता।

=====

दंड प्रक्रिया संहिता---धारा 482, 245---भारतीय दंड संहिता---धारा 498 ए---हिंदू विवाह अधिनियम---धारा 9---आईपीसी की धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए संज्ञान लेने और याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल निर्वहन याचिका को खारिज करने के आदेश को रद्द की याचिका---ओ.पी. नंबर -2 द्वारा लगाए गए आरोप मुख्य रूप से उसके पति के इर्द-गिर्द घूमते थे और उसके द्वारा उठाई गई मुख्य शिकायत याचिकाकर्ताओं द्वारा शादी से पहले अपने पति की मानसिक बीमारी को छुपाना था---ओ.पी. नंबर 2 ने पैसे की मांग और उसके साथ कथित रूप से की गई अन्य क्रूरता के आरोपों में याचिकाकर्ताओं की कोई विशिष्ट भूमिका का खुलासा नहीं किया, इसलिए, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ उनके आरोप पूरी तरह से सामान्य और सर्वव्यापी रहे---यह एक स्वीकृत स्थिति है कि शादी के बाद, ओ.पी. नंबर 2 अपने पति के साथ अपने ससुराल में केवल 10-15 दिनों के लिए रही दुल्हन के लिए अपने दूल्हे और उसके ससुराल वालों के स्वभाव और व्यवहार को समझना बहुत कठिन होगा और ऐसा प्रतीत होता है कि ओ.पी. नंबर 2 के पति के कुछ असामान्य व्यवहार के कारण, जो ओ.पी. नंबर 2 को पसंद नहीं था, उसने अपने पति का साथ छोड़ दिया और जब उसके पति ने वैवाहिक जीवन की बहाली के लिए वैवाहिक मुकदमा दायर किया तो उसने शिकायत दर्ज कराई--- ओ.पी. नं. 2 ने प्रतिशोध में द्वेषपूर्ण इरादे से शिकायत दर्ज कराई है, इसलिए, याचिकाकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पूरी तरह से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा--- वर्णित तथ्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं--- विवादित आदेश अलग रखे गए---याचिकाकर्ताओं को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त किया गया---याचिका स्वीकार की गई। (पैरा 5)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

11 30-01-2025 याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री रवींद्र कुमार, राज्य के विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री कुमार उदय प्रताप और विरोधी पक्ष सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री संजीव कुमार को सुना।

2. वर्तमान आपराधिक विविध याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 (संक्षेप में 'सी.आर.पी.सी.') के तहत अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी भागलपुर के दिनांक 12-8-2016 के आदेश को रद्द करने के अनुरोध के साथ दायर की गई है। जो शिकायत मामला संख्या 2679/2015 के संबंध में विद्वान अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर (संक्षेप में 'एस.डी.जे.एम. भागलपुर') द्वारा पारित किया गया, जिसके तहत और जिसके तहत विद्वान एस. डी. जे. एम. ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए (संक्षेप में 'भा. दा. वि.') के तहत अपराध का संज्ञान लिया है और परिणामस्वरूप, उन्हें उक्त अपराध के लिए तलब किया गया है। बाद में, याचिकाकर्ताओं के आरोपमुक्त करने के अनुरोध को खारिज करते हुए विद्वान एस. डी. जे. एम., भागलपुर द्वारा पारित दिनांकित 08.01.2024 आदेश को दरकिनार करने के लिए एक अतिरिक्त अनुरोध के साथ वाला एक अंतर्वर्ती आवेदन सं. 1/24 दायर किया गया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस याचिका को दायर करने के बाद, याचिकाकर्ता संख्या 4, अर्थात्, महारानी देवी की मृत्यु हो गई, इसलिए, उनका नाम तत्काल याचिका के शीर्षक से दिनांक 11-03-2024 हटा दिया गया था।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं में याचिकाकर्ता संख्या 1, 2 और 3 क्रमशः विरोधी पक्षकार संख्या 2 के ससुर, सास और ससुर हैं, याचिकाकर्ता संख्या 5 विरोधी पक्षकार संख्या 2 के पति के चाचा हैं और याचिकाकर्ता संख्या 6 अन्य याचिकाकर्ताओं के सह-ग्रामीण हैं और इन सभी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई विशिष्ट आरोप नहीं है और विरोधी पक्षकार संख्या 2 ने उनके खिलाफ सामान्य और सर्वव्यापी आरोप लगाए हैं और अभियोजन पक्ष के अनुसार, याचिकाकर्ता नंबर 6 ने विरोधी पक्ष सं. 2 और उनके पति के बीच शादी की बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। विवाह के बाद, विरोधी पक्ष सं. 2 अपने पति के साथ उसके ससुराल में केवल कुछ दिनों के लिए रही थी और यह अविश्वसनीय है कि विरोधी पक्ष सं. 2 में उसके ससुराल वालों के साथ रहने की उस छोटी अवधि में, याचिकाकर्ता उसे प्रताड़ित कर सकते थे या भा.दा.वि. की धारा 498 ए के तहत अपराध को आकर्षित करके कोई गलत काम कर सकते थे। वास्तव में, विरोधी पक्ष सं. 2 ने शादी के ठीक बाद केवल दस दिनों तक अपने साथ में रहने के बाद अपने पति को छोड़ दिया और रहने की उस छोटी अवधि के दौरान, विरोधी पक्ष सं. 2 का आचरण उसके वैवाहिक घर में सामान्य नहीं था और उसके बाद, विरोधी पक्ष सं. 2 के पति ने विरोधी पक्ष सं. 2 को वापस लाने के लिए कई अनुरोध करके अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन वह वाराणसी में उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि उसने दो लाख रुपये की अनुचित मांग की और उसने पति के साथ दुर्व्यवहार किया जब उसने विरोधी पक्ष सं. 2 को अपने घर वापस लाने की कोशिश की और इन परिस्थितियों में विरोधी पक्ष सं. 2 के पति में हताशा की भावना पैदा हो गई और आखिरकार, उसने आत्महत्या कर ली। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विरोधी पक्ष सं. 2 के पति ने आत्महत्या करने से पहले पारिवारिक अदालत, भागलपुर में एक वैवाहिक मामला नंबर 316/2015 दायर किया था जिसमें विरोधी पक्ष सं. 2

पेश हुई लेकिन उसका व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं रहा और उसने वैवाहिक जीवन की बहाली के लिए उसके पति की प्रार्थना को तुच्छ आरोप के आधार पर अस्वीकार कर दिया। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि तत्काल मामला विरोधी पक्षकार संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत पर आधारित है जिसमें विरोधी पक्षकार संख्या 2 द्वारा कई घटनाओं का वर्णन किया गया है, लेकिन सभी घटनाएं केवल विरोधी पक्षकार संख्या 2 के पति के इर्द-गिर्द घूमती हैं और धन या क्रूरता की कथित मांग करने में इनमें से किसी भी याचिकाकर्ता की कोई विशिष्ट भूमिका का खुलासा नहीं किया गया है, हालांकि विरोधी पक्षकार संख्या 2 ने कुछ चेकों का विवरण दिया है, लेकिन शादी से पहले की अवधि से संबंधित सभी चेक दिए हैं। विरोधी पक्ष सं. 2 ने मुख्य रूप से अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसका पति मानसिक रूप से बीमार था और मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था जिसे याचिकाकर्ताओं ने उसके और उसके माता-पिता के साथ छुपाया था। लेकिन इस आरोप के समर्थन में, विरोधी पक्ष सं. 2 द्वारा उनके सीधे सादे बयान के अलावा कोई दस्तावेजी सबूत नहीं दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि विरोधी पक्ष सं. 2 का पति एक मेधावी छात्र था और उसे सिंडिकेट बैंक में परिवीक्षाधीन अधिकारी (पी. ओ.) के पद पर चुना गया था और उसके पास टी.एन.बी. विश्वविद्यालय द्वारा वाणिज्य में पी. एच. डी. की डिग्री भी थी और उसने एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा से एम.बी.ए. किया था और इस संबंध में, प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ पूरक हलफनामा दायर किया गया है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि निचली अदालत के समक्ष आरोप गठन करने से पहले बयान दर्ज करते समय। आरोप, शिकायतकर्ता (विरोधी पक्ष सं. 2) ने कहा कि वह तलाक लेना चाहती थी और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन क्योंकि उन्होंने मामला दर्ज किया था, इसलिए उसे मामला दर्ज करने के लिए मजबूर किया गया। इस कथित तथ्य से, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि विरोधी पक्ष

सं.2 ने जवाबी कार्रवाई में उसका मामला दर्ज किया। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि यदि याचिकाकर्ताओं पर मुकदमा चलाया जाता है तो यह अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा क्योंकि विरोधी पक्षकार संख्या 2 ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपना मामला दायर किया है और इन याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना हरियाणा राज्य और अन्य बनाम अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अंतर्गत आती है जो भजन लाल और अन्य ने 1992 के सप्लीमेंट (1) एस. सी. सी. 335 में रिपोर्ट है, जिसमें यह फैसला सुनाया गया था कि जहां आरोपी से बदला लेने के लिए दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है और निजी और व्यक्तिगत रंजिश के कारण उसे परेशान करने की दृष्टि से ऐसी कार्यवाही को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

4. दूसरी ओर, विरोधी पक्ष सं. 2 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने इस याचिका का जोरदार विरोध किया है और कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने विरोधी पक्ष सं. 2 के वैवाहिक जीवन को नष्ट कर दिया है क्योंकि उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं था और इसे याचिकाकर्ताओं ने उससे और उसके परिवार के सदस्यों से छिपा दिया था। विरोधी पक्ष सं. 2 के विवाह में, उनके माता-पिता द्वारा एक बड़ी राशि खर्च की गई थी। और विरोधी पक्ष सं. 2 के पिता ने याचिकाकर्ताओं की सभी वैध और अवैध मांगों को केवल विरोधी पक्ष सं. 2 के वैवाहिक जीवन को खुश करने की दृष्टि से पूरा किया, लेकिन चीजें गलत हो गईं और विरोधी पक्ष सं. 2 के पति की आत्महत्या के तथ्य से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि विरोधी पक्ष सं. 2 का पति मानसिक बीमारी से पीड़ित था और विरोधी पक्ष सं. 2 के लिए अपने पति की मानसिक बीमारी से संबंधित प्रासंगिक कागजात प्राप्त करना संभव नहीं था और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ धारा 498ए भा.द.वि. के तहत अपराध के साथ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामग्री है और उक्त अपराध का संज्ञान लेने के साथ-

साथ याचिकाकर्ताओं के आरोपमुक्त करने की प्रार्थना को खारिज करने वाले आदेश सही ढंग से पारित किए गए हैं।

5. दोनों पक्षों को सुना और आक्षेपित आदेशों को पढ़ा। यह मामला याचिकाकर्ताओं के खिलाफ विरोधी पक्ष सं. 2 द्वारा दायर शिकायत पर आधारित है। शिकायत में, विरोधी पक्ष सं. 2 ने पूरे आरोपों का विस्तृत तरीके से वर्णन किया, लेकिन उसके द्वारा लगाए गए सभी आरोप मुख्य रूप से उसके पति के इर्द-गिर्द घूमते थे और उसके द्वारा उठाई गई मुख्य शिकायत याचिकाकर्ताओं द्वारा शादी से पहले उसके पति की मानसिक बीमारी को छिपाना है। याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने पूरक हलफनामे के साथ दायर किए गए उपरोक्त दस्तावेजों के आलोक में, यह स्पष्ट रूप से विदित है कि विरोधी पक्ष सं. 2 का पति एक मेधावी व्यक्ति था। चूंकि वे उच्च शिक्षित थे और उन्हें एक प्रतिष्ठित बैंक में पी. ओ. के पद पर नौकरी मिली थी और उनका शोध पत्र भी प्रकाशित हुआ था, जो सामान्य रूप से मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। विरोधी पक्ष सं. 2 ने याचिकाकर्ताओं की किसी भी विशिष्ट भूमिका का खुलासा नहीं किया कि उनके साथ कथित रूप से धन की मांग और अन्य क्रूरता की गई थी, इसलिए, उनके आरोप याचिकाकर्ताओं के खिलाफ पूरी तरह से सामान्य और सर्वव्यापी रहे। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि विरोधी पक्ष सं. 2 के पति ने पहले हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक मुकदमा दायर किया और उसके बाद विरोधी पक्ष सं. 2 द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और आरोप तय करने से पहले बयान दर्ज करते हुए विरोधी पक्ष सं. 2 ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह मामला दर्ज नहीं करना चाहती थी, बल्कि वह तलाक लेना चाहती थी, लेकिन उसके खिलाफ उसके पति द्वारा मामला दर्ज किया गया था, इसलिए उसे मामला दर्ज करना पड़ा। इस कथित तथ्य से, ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी पक्ष सं. 2 ने जवाबी कार्रवाई में अपना मामला दायर किया और

अपना बयान दर्ज करते समय, उसने याचिकाकर्ताओं के कथित क्रूर व्यवहार में उनकी विशिष्ट संलिप्तता दिखाने वाले किसी भी कार्य का खुलासा नहीं किया और उसने बस इतना कहा कि उसकी शादी के स्वागत के समय, उसके पति का आचरण अच्छा नहीं था क्योंकि वह चिल्लाता था और जब वह अपने माता-पिता के घर वापस आयी थी तो उसका पति उसे जमालपुर वापस ले आया और उससे कहा कि वह अपनी नौकरी को छोड़ देगा। चिकाकर्ताओं के खिलाफ उस बयान को दर्ज करते समय, विरोधी पक्ष सं. 2 ने केवल यह खुलासा किया कि उनके पति के परिवार के सदस्यों ने उन पर अपने पति को उनकी नौकरी छोड़ने के लिए कहने का दबाव डाला था। कथित तथ्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भा.दा.वि. की धारा 498ए के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि यह एक स्वीकृत स्थिति है कि विवाह के बाद, विरोधी पक्ष सं. 2 अपने पति के साथ अपने ससुराल में केवल 10-15 दिनों के लिए रही थी और इतने कम समय में, एक दुल्हन के लिए अपने दूल्हे और अपने ससुराल वालों की प्रकृति और व्यवहार को समझना बहुत मुश्किल होगा और ऐसा प्रतीत होता है कि विरोधी पक्ष सं. 2 के पति के कुछ असामान्य व्यवहार के कारण, जो विरोधी पक्ष सं. 2 को पसंद नहीं था, उसने अपने पति का साथ छोड़ दी और जब उसके पति ने वैवाहिक जीवन की बहाली के लिए वैवाहिक मुकदमा दायर किया तो शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे बढ़ गई। उपरोक्त वर्णित किए गए तथ्यों से प्रकट होने वाली इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि विरोधी पक्षकार संख्या 2 ने अपना शिकायत मामला केवल प्रतिशोध में दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया है, जिसमें विवादित आदेश से पारित किए गए हैं, इसलिए याचिकाकर्ताओं को भा.दा.वि. की धारा 498ए के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पूरी तरह से अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और जो विद्वान दंडाधिकारी द्वारा आरोप तय करने से पहले उन

साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ भा.दा.वि. की धारा 498 ए के तहत कोई अपराध नहीं बनता है और वे सभी आरोपों से मुक्त होने के हकदार हैं और विद्वान दंडाधिकारी ने द.प्र.सं.की धारा 245 के तहत उन्हें दी गई शक्ति का उचित तरीके से प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार, दोनों विवादित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है और याचिकाकर्ताओं को शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से मुक्त कर दिया जाता है। नतीजतन, तत्काल याचिका को अनुमति दी जाती है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

वार्षिकी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।